व्यापार और मानव अधिकारों पर IBA का अद्यतनिक मार्गदर्शन नोट: बदलते परिदृश्य में वकीलों की भूमिका

अनुभाग 1: परिचय

1. 2016 में, IBA ने व्यापार वकीलों के लिए एक व्यावहारिक गाइड व्यापार और मानव अधिकारों पर जारी किया ताकि 2011 संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और मानव अधिकारों पर मार्गदर्शक सिद्धांत (UNGPs) और कानूनी पेशे के लिए संबंधित मानक के निहितार्थ का आकलन किया जा सके।[1] इस गाइड मे UNGPs के व्यापक उत्थान, उनके राज्यों, व्यवसायों और नागरिक समाज के लिए बढ़ता महत्व और कानून में उनके समावेश का उल्लेख किया गया। इसमें UNGPs का कानूनी अभ्यास पर प्रभाव की चर्चा की गई। इसके सहित एक संदर्भ अनुलग्नक था जिसमें इन मुद्दों की और विस्तार से चर्चा की गई।

2. कानूनी पेशे के लिए UNGPs की प्रासंगिकता की तेज़ी से वृद्धि हुई है, जैसा कि कई कारकों से स्पष्ट है - जैसे घरेलू स्तर पर अनिवार्य मानवाधिकारों उचित परिश्रम और रिपोर्टिंग कानून का अधिनियमन किंतु यह अलौकिक रूप से कंपनियों पर भी लागू होता है, देखभाल के कर्तव्य, UNGPs पर आधारित कॉर्पोरेट दायित्व और कानूनी ज़िम्मेदारी के दावे तथा संबंधित मानक या तो स्थानीय एवं/ विदेशी, और गंभीर मानवाधिकारों की मान्यता जो की पर्यावरणीय नुकसान कर रही है, जैसे जलवायु परिवर्तन।

3. राज्य, निवेशक, ऋणदाता, उपभोक्ता, समुदाय और नागरिक समाज तेज़ी से व्यापार मानवाधिकार प्रदर्शन का आकलन कर रहें हैं एवं UNGPs को आधिकारिक वैश्विक मानक के रूप में अधिकतम मान्यता दे रहे हैं।

4. यह मार्गदर्शन नोट 2016 की व्यावहारिक गाइड पर आधारित उसके प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में दोहराता है एवं स्नैपशॉट प्रदान करता है उभरते रुझान और कानून का जो व्यापार वकीलों के लिए विश्व स्तर पर प्रासंगिक हैं।

अनुभाग 2: संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और मानव अधिकारों पर मार्गदर्शक सिद्धांत (UNGPs)

5. 2005 में, तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव, कोफी अन्नान ने, हार्वर्ड केनेडी स्कूल प्रोफेसर जॉन रग्गी को व्यापार और मानव अधिकारों पर अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया (**SRSG**)। उन्होंने प्रोफ. रग्गी को एक ढांचा के रचना का कार्य दिया जो राज्य और व्यापार के मानवाधिकार के प्रति संबंधित कर्तव्यों एवं ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट करे।

6. नतीजतन, छह वर्ष के बहुहितधारक परामर्श, अनुसंधान और पायलट परियोजनाओ के परिणामस्वरूप, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सर्वसम्मति से SRSG के UNGPs का समर्थन किया।[2] UNGPs संचालन करते हैं SRSG की रक्षा, सम्मान और उपचार ढांचा का, जो की परिषद द्वारा 2008 मे अनुमत किया गया था। इस ढांचे के तहत, UNGPs स्पष्ट करता है मानव अधिकार की रक्षा के लिए राज्यों के कर्तव्य (**स्तंभ एक**), व्यवसायों की जिम्मेदारी उनके संचालन और मूल्य श्रृंखला में मानवाधिकारों का सम्मान करना (**स्तंभ दो**) और हितधारकों द्वारा उपाय हेतु अधिक पहुंच की आवश्यकता (**स्तंभ तीन**)।

7. स्तंभ एक के तहत, राज्यों का कर्तव्य कि वह मानवाधिकार की रक्षा करे अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा लगाया गया एक कानूनी कर्तव्य है। इसका पालन किया जाता है नीतियों, विनियमों और अधिनिर्णय के माध्यम से मानव अधिकारों के दुरुपयोग को रोकना, जांच करना, दंडित करना और निवारण करना (UNGP 1)।

8. स्तंभ दो के तहत, सभी व्यावसायिक उद्यमों की, उनके आकार, क्षेत्र, परिचालन संदर्भ, स्वामित्व और संरचना के बावजूद अपने संचलन एवं मूल्य श्रृंखला में मानव अधिकार का सम्मान करने की ज़िम्मेदारी है (UNGP 14)। इसका मतलब है कि उन्हें सार्वजनिक रूप से मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और उस प्रतिबद्धता को उनके शासन, नेतृत्व और संस्कृति में शामिल करना चाहिए, और उचित परिश्रम के इस्तेमाल से प्रतिकूल मानवाधिकार की पहचान, रोक या प्रभावों को कम करना चाहिए जिसमें वे शामिल हैं या हो सकते हैं। मानवाधिकार पर उचित परिश्रम एक सतत, हितधारक-केंद्रित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यवसाय अपनी संभावित और वास्तविक मानव अधिकारों के प्रभाव पहचान करता है, एक एकीकृत फैशन में उनका जवाब देता है, एवं अपने प्रदर्शन पर निगरानी और रिपोर्ट करता है।

9. स्तंभ तीन के तहत, राज्यों का प्राथमिक कर्तव्य है मानवाधिकारों के दुरुपयोग को दूर करना, लेकिन व्यवसायों से उम्मीद की जाती है कि वे वैध प्रक्रियाओं के माध्यम से उपाय

प्रदान करे या सहयोग करे जहां वे प्रतिकूल प्रभावों का कारण है या योगदान दिया है (UNGP 22)। ऐसा करने के लिए उपचार प्रक्रिया मे, व्यवसाय द्वारा ही या दूसरों के सहयोग के साथ सक्रिय कार्य की आवश्यकता होती है। उपचार कई रूप ले सकता है और यह न्यायिक या गैर-न्यायिक हो सकता है। व्यवसायों से उम्मीद है कि वे प्रभावी परिचालन स्तर पर समुदायों और व्यक्तियों के व्यथा निवारण क्रियाविधि मे भाग ले ताकि समस्याओं का शीघ्र समाधान कर सके।

10. हालांकि अपने आप में यह नरम कानून है, UNGPs को मानव अधिकार की तुलना में व्यवसायों और राज्यों की भूमिकाओं के लिए आधिकारिक वैश्विक मानक स्वीकृत किया जाता है। मानव अधिकार का सम्मान करने के लिए व्यावसायिक जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों से होती है, जैसा कि सम्मेलनों, संधियों में, और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानक मे व्यक्त किया गया है (UNGP 12)। उन्होंने प्रेरित किया है या वे बाध्यकारी कानूनों में परिलक्षित हुए हैं, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

11. UNGPs एक जीवंत दस्तावेज हैं और इनका इरादा था कि राज्यों, व्यापार और नागरिक समाज के यात्रा के माध्यम से गतिशील परिवर्तन को शुरू करना। उनके व्याख्या और आवेदन को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानक के समय के साथ विकास और अभिव्यक्ति को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसमें शामिल हैं, उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा की भारी मतदान जुलाई 2022 मे एक प्रस्ताव के पक्ष में जिसमे मान्यता दि गई एक स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के लिए मानव अधिकार की, जिसका उल्लंघन कई अन्य मानव अधिकारों का आनंद रोकता है।[3] गंभीर जलवायु परिवर्तन के वैश्विक मानवाधिकार पर प्रभाव, प्रदूषण और जैव विविधता का नुकसान, जिसमें व्यवसाय शामिल हैं, इसके प्रमुख उदाहरण हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा का वोट कानूनी रूप से अपने आप में बाध्यकारी नहीं हो सकता है, यह UNGP 12 पर टिप्पणी के रूप में 'अतिरिक्त मानक' माना जाता है जिसके लिए व्यवसाय की मानवाधिकारों का सम्मान करने की जिम्मेदारी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

12. उनके समर्थन के बाद से, UNGPs, और विशेष रूप से मानवाधिकार सम्मान के लिए व्यावसायिक जिम्मेदारी, तेज़ी से विधियों, विनियमों, न्यायिक और अर्ध-न्यायिक अभिव्यक्ति मे देखभाल के कानूनी कर्तव्य, कॉर्पोरेट जिम्मेदारी, बहु-हितधारक मानदंड, निवेशकों और बैंकों के निर्णय, प्रमुख कंपनियों की प्रथाओं और नीतियों, और नागरिक समाज की वकालत में परिलक्षित या शामिल हो गए हैं। एसे ही, वे उन संदर्भों में पक्के कानून के दायित्व हो जाते हैं।

13. 2011 के बाद, राज्यों ने स्वैच्छिक व्यवसाय को प्रोत्साहित किया राष्ट्रीय कार्य योजनाओं (**NAPs**) को प्रख्यापित करके जो UNGPs को लागू करने के लिए उनकी योजनाओं की रूपरेखा बताता है। लेखन के समय, दुनिया भर के लगभग 40 देशों ने NAPs जारी किए हैं - सबसे हाल ही में युगांडा, केन्या और जापान हैं।

14. जैसे-जैसे UNGPs की समझ परिपक्व होती गई, कुछ राज्यों ने मानव अधिकार के उचित परिश्रम सहित गैर-अनुपालन के लिए प्रतिबंध और हितधारकों के लिए उपचार अनिवार्य करने के लिए कानून बनाए हैं। 2017 में फ़्रांस ने एक कानून पेश किया, उसके बाद जर्मनी और नॉर्वे ने 2021 में, और 2023 में स्विट्जरलैंड ने प्रभावी किया। फ्रांसीसी सतर्कता कानून UNGPs को संदर्भित करता है प्रारंभिक टिप्पणियो में और स्पष्ट रूप से शामिल करता है लोगों के लिए सभी जोखिमों की पहचान करना, जैसे पर्यावरणीय जोखिम, और सबसे गंभीर जोखिमों को रोकने के उपाय, जैसे पर्यावरणीय क्षति। इसी तरह के अनिवार्य उचित परिश्रम विधायी प्रस्ताव ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड, यूके, और सबसे महत्वपूर्ण, यूरोपीय संघ में लंबित हैं। इस अद्यतन को लिखने के समय, यूरोपीय संघ के कॉर्पोरेट स्थिरता पर उचित परिश्रम की मसौदा निर्देश (**CSDDD**) का प्रस्ताव है अनिवार्य मानव अधिकार और पर्यावरणीय उचित परिश्रम; यह यूरोपीय संघ की कंपनियों के साथ-साथ गैर-यूरोपीय संघ की कंपनियों पर भी लागू होगा जिसकी यूरोपीय संघ के एकल बाजार में वार्षिक बिक्री कुछ थ्रेसहोल्ड से अधिक है।[4] इसके अतिरिक्त, 5 जनवरी 2023 को कॉर्पोरेट स्थिरता रिपोर्टिंग निर्देश (**CSRD**) लागू हुआ, जिसके अंतर्गत कंपनियों द्वारा सामाजिक और पर्यावरण रिपोर्टिंग पर नियमों का आधुनिकीकरण और मज़बूत किया गया।[5] CSRD के अनुसार, 31 जुलाई 2023 को, यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय स्थिरता रिपोर्टिंग मानक (**ESRS**) प्रस्तुत किया, जो अगर और जब अनुमोदित होगा, तो अपेक्षित होगा की उल्लेखित व्यवसाय पर्यावरण और लोगों पर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण के रूप में विचार करेंगे, जिसमे शामिल होंगे उनके अपने श्रमिक, मूल्य श्रृंखला श्रमिक, प्रभावित समुदाय, और उपभोक्ता और अंतिम उपयोगकर्ता।

15. इसके अलावा, घरेलू कानून सामने आए हैं जो की मानवाधिकारों का हनन करते है जैसे आधुनिक दासता रिपोर्टिंग कानून, मैग्निट्स्की कानून और रीति-रिवाज कार्यालय जब्ती या निषेधित आयातित माल का बाल श्रम द्वारा निर्माण।

16. इन घटनाओं ने अन्य देशों में क्रॉस-परागण और समान मार्गदर्शन तथा कानूनों का उत्पन्न किया है। उदाहरण के लिए, जापान ने देर 2022 मे मानव अधिकार उचित

परिश्रम पर गैर-बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी किया, जिसमे में यूरोप मे उभरते उचित परिश्रम कानून और विश्व स्तर पर मजबूर श्रम कानूनों का उदाहरण देते हुए व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता को उजागर किया गया।

17. अंत में, जब कंपनियां सार्वजनिक रूप से मानवाधिकार सम्मान के लिए प्रतिबद्ध होती हैं, वे अपने मूल्य श्रृंखला के सदस्यों से वही करने की अपेक्षा करते हैं और उनके अनुबंध और समझौतों मे UNGP-संबंधित मानवाधिकार प्रदर्शन मानकों को शामिल करते है। इसके कारण खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के नेटवर्क में मानव अधिकार के निजी वाणिज्यिक कानून का विकास हो रहा है।

अनुभाग 3: उपाय तक पहुंच

18. **न्यायिक निर्णय।** कई न्यायालयों ने राज्यों के लोगों और समुदायों के प्रति व्यवसाय-संबंधित मानवाधिकारों के दुरुपयोग से रक्षा के कर्तव्य को मान्य करने वाले निर्णय दिए है और UNGPs के तहत मानव अधिकार का सम्मान करने की व्यवसायों की जिम्मेदारी पर पुष्टि दी है। पूरी तरह से नहीं किंतु, उदाहरण के लिए:[6]

    a. *SERAP v. Nigeria*:[7] 2012 में कोर्ट ऑफ जस्टिस पश्चिम अफ्रीकी आर्थिक समुदाय के राज्यों (ECOWAS) ने यह मान्य किया कि नाइजीरिया राज्य के लिए अनिवार्य है की वह एक तेल छलकाव परीस्तिथि को 'रोकने या निपटने' के लिए 'उन लोगों को जवाबदेह ठहराए जो इस स्थिति का कारण है और सुनिश्चित करे कि पीड़ितों के लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है'।

    b. *Vedanta Resources Plc v. Lungowe; Okpabi & others v. Shell*:[8] 2019 और 2021 में यूके सुप्रीम कोर्ट ने दो ऐतिहासिक निर्णय जारी किए, जिसमें कहा गया कि एक मूल कंपनी का पर्यावरणीय क्षति से संबंधित दावेदार और अपने विदेशी गौण द्वारा मानवाधिकारों के हनन की प्रति देखभाल का कर्तव्य हो सकता है, कम से कम जहां मूल कंपनी गौण के कार्यों की निगरानी करते है, यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाते है कि गौण मूल की नीतियों को लागू करे, और नुकसान को रोकने के लिए सक्रिय कदम लेने में विफल होते है।

    c. *Nevsun Resources Ltd v. Araya*:[9] 2020 में, कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया कि प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून, जैसे की मानवता के खिलाफ अपराधों का निषेध,

जबरन श्रम और यातना, कनाडा के कानून का हिस्सा हैं, और विदेशी संचालन के परिणामस्वरूप कनाडा की कंपनियां इन मानकों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हो सकती हैं।

d. *Miskito Divers (Lemoth Morris et al) v. Honduras:*[10] 2021 मे मानव अधिकारों पर इंटर-अमेरिकन कोर्ट ने राज्यों पर कर्तव्य लागू करने के पक्ष मे फैसला सुनाया कि वे अपने व्यवसायों को UNGPs के बुनियादी अवधारणाओ के अनुसार विनियमित करें।

e. *In re University of Stellenbosch Legal Aid Clinic, et al (2015):*[11] 2015 में, दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय ने माना कि UNGPs के तहत, राज्यों को निश्चित रूप से व्यापार द्वारा मानव अधिकारों के दुरुपयोग को रोकना और उपचार के लिए बाधाओं को कम करना चाहिए। इसलिए कोर्ट ने एक दक्षिण अफ्रीकी ऋण वसूली कानून लागू करने के लिए मना कर दिया जो की कानूनी सलाह द्वारा तैयार किया गया था जिससे माइक्रोलेंडर्स शिकारी, अनुचित और भ्रामक ऋण संग्रह प्रथाओं को लागू कर सके जो की हजारों गरीब कर्जदारनो से उचित प्रक्रिया को नकारता है। अपील पर, दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह क़ानून असंवैधानिक नहीं था क्योंकि ऋणदाताओं ने इसका गलत अर्थ निकाला और इसका गलत इस्तेमाल किया था।

f. *Oguru et al v. Shell:*[12] 2021 में, हेग के अपील की अदालत ने एक डच कंपनी को अपने अफ्रीकी गौण कंपनी द्वारा किए गए तेल छलकाव के लिए उत्तरदायी पाया, *Vedanta*, ऊपर का उदाहरण देते हुए। अपील अभी भी जारी है।

g. *Milieudefensie v. Shell:*[13] 2021 में, हेग के जिला न्यायालय ने एक तेल कंपनी को अपने CO2 उत्सर्जन को कम करने का आदेश दिया, एक अलिखित कानून के नियम को लागू किया जो की डच सिविल कोड के तहत सामाजिक आचरण से संबंधित है, तथा UNGPs और अन्य नरम एवं पक्के कानून का उपयोग करके कंपनी के देखभाल के कर्तव्य को परिभाषित किया। अपील जारी है।

19. **न्यायिक दावे जो प्रक्रिया में हैं।** लोगों और समुदाय के न्यायिक दावे जो UNGPs का संदर्भ देते हैं और/ या मानवाधिकारों के दुरुपयोग के उपचार की मांग करते है विभिन्न क्षेत्राधिकार मे लंबित है। उदाहरण स्वरूप:

a. 2020 में एक लीड खदान से कथित तौर पर प्रभावित जाम्बियन समुदाय की ओर से जोहान्सबर्ग उच्च न्यायालय मे दक्षिण अफ्रीकी खनन कंपनी के खिलाफ एक वर्ग कार्यवाही दायर की गई थी।[14]

b. 2023 में, एक इंडोनेशियाई द्वीप के निवासियो ने स्विट्जरलैंड मे एक स्विस कंपनी पर जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते स्तर और हिमनद झील के बाढ़ से खतरों के लिए मुकदमा दायर किया, जिसकी प्रेरणा एक एसे ही मुकदमे से मिली जो की जर्मनी में एक जर्मन बिजली प्रदाता के खिलाफ नुकसान भरपाई के लिए की गई थी।[15]

c. फ्रांस में, मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के संबंध में कई मामले लंबित हैं, जिनमें शामिल हैं फ्रांसीसी सतर्कता कानून के तहत निकालने वाले कृषि व्यवसाय, ऊर्जा और बैंकिंग क्षेत्र मे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पर्यावरणीय क्षति, फ़्रांस के बाहर होने वाले नुकसान सहित।[16]

d. कई यूरोपीय अधिकार-क्षेत्र में (जर्मनी और यूके सहित) 2015 में ब्राजील में हुए बांध टूटने के मामले पर अदालतों की कार्यवाही चल रही है (आमतौर पर 'मारियाना बांध ढहना' के रूप में जाना जाता है)।

e. जबरन मजदूरी मे कथित मिलीभगत के लिए परिधान क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कई देशों में आपराधिक जांच का सामना करना पड़ रहा है।

f. वस्त्र उद्योग मे श्रमिकों के प्रतिनिधित्व करने वाले एक बांग्लादेशी संघ ने जर्मन ड्यू डिलिजेंस अधिनियम के तहत कारखानों की सुरक्षा की निगरानी करने में विफल होने के लिए कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।

20. **गैर-न्यायिक शिकायत तंत्र।** UNGPs यह भी उल्लेख करते है कि गैर-न्यायिक शिकायत तंत्र द्वारा उपचार प्रदान किया जा सकता है यदि वे हैं वैध, सुलभ, अनुमानित, न्यायसंगत, पारदर्शी, अधिकार-संगत हैं, निरंतर सीखने का एक स्रोत है और, परिचालन स्तर पर शिकायत तंत्र के मामले में, प्रतिबद्धता और संवाद पर आधारित है (UNGP 31)।

21. **मध्यस्थता।** 2013 में बांग्लादेश के राणा प्लाजा मे परिधान कारखाना के ढहने के बाद, ब्रांड और ट्रेड यूनियनों ने एक बहुपक्षीय समझौते में प्रवेश किया, अब अंतर्राष्ट्रीय समझौते के रूप में जाना जाता है, जो की कारखानों की सुरक्षा की स्थिति मे सुधार करने के लिए

है। यह विवादों की बाध्यकारी मध्यस्थता के लिए प्रदान करता है। हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के द्वारा कम से कम दो मध्यस्थता प्रारंभ और प्रशासित की गई है। आम तौर पर, अभी तक वाणिज्यिक मध्यस्थता UNGP 31 के गैर-न्यायिक शिकायत तंत्र के तहत उस प्रभावशीलता मानदंड को मेल नहीं कर पाए है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों के एक सक्रिय समूह द्वारा 2019 मे प्रकाशित व्यापार और मानव अधिकारों के मध्यस्थता पर हेग नियम का लक्ष्य है उन मानदंडों को पूर्ण करना एवं व्यापार और मानवाधिकार विवादों को हल करने मे मध्यस्थता के उपयोग को बढ़ावा देना।[17]

22. **द्विपक्षीय निवेश संधि विवाद।** UNGPs का द्विपक्षीय संधि विवादों से उत्पन्न विदेशी निवेशकों और मेजबान राज्यों के बीच, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, विकास और खनन क्षेत्रों मे अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पर भी कर्षण बढ़ रहा है; देखे, *Urbaser v. Argentina* and *David Aven et al v. Costa Rica*।[18] अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थो मे भी आवश्यकता और आनुपातिकता के सिद्धांतों का आह्वान करने की प्रवृत्ति है जिससे कि आवश्यकता या आनुपातिकता के सिद्धांतों के तहत विदेशी निवेशकों के अधिकारों की रक्षा और मानव अधिकार की रक्षा की आवश्यकता के बीच संतुलन बना रहे। साथ ही नए द्विपक्षीय निवेश संधियां भी लिखी गई है। उदाहरण के लिए, जुलाई 2022 में अफ्रीका आर्बिट्रेशन अकादमी ने अफ्रीकी राज्यों के लिए अपना मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि लॉन्च किया जिसका उद्येश्य है स्थायी निवेश और स्थानीय संतुलन और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को उबंटू सिद्धांत पर आधारित बढ़ावा देना।[19]

23. **OECD राष्ट्रीय संपर्क बिंदु (NCPs)।** कंपनियों और हितधारकों ने स्वैच्छिक गैर-न्यायिक OECD NCP विवाद तंत्र के उपयोग से व्यापार और मानवाधिकार विवादो का हल किया है। 2023 मे अद्यतनित, बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर OECD दिशानिर्देश, UNGPs के मानव अधिकार उचित परिश्रम प्रक्रिया को ट्रैक करते है।[20] यह स्वैच्छिक हैं लेकिन व्यापक रूप से पालन किए जाते है। एक कंपनी का OECD दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप NCP को शिकायत की जा सकती है किसी भी (वर्तमान में) 51 में से एक देशों में जो OECD दिशानिर्देशों का पालन करते है। यह शिकायतें अक्सर मध्यस्थता, समझौते और कंपनी के अनुपालन के बारे में बयान, और NCP द्वारा उनकी सिफारिशों की निगरानी पर पथ प्रदर्शित करते है।

24. **संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की विशेष प्रक्रियाएं।** संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रक्रियाएं स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है विषयगत या देश-

विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा मानवाधिकारों के सलाह पर रिपोर्ट करना। जून 2023 मे, संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और मानवाधिकार पर कार्य समूह, एक स्वच्छ, स्वस्थ और स्थायी पर्यावरण से संबंधित मानवाधिकार दायित्व पर विशेष प्रतिवेदक, और सुरक्षित पानीय जल के मानवाधिकारों पर विशेष प्रतिवेदक ने, एक राज्य के स्वामित्व तेल कंपनी को पत्र भेजा जिसके तहत उन्हे आरोपों का जवाब देने की आवश्यकता थी कि उनके जीवाश्म ईंधन उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास से राज्य की अंतरराष्ट्रीय कानून तहत कर्तव्यों एवं पेरिस समझौते के तहत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर बाधाएं आ रही है।[21]

अनुभाग 4: यह तेज़ी से बदलता परिदृश्य वकीलों की भूमिकाओं को कैसे प्रभावित करता है?

25. कानून गतिशील है; जिसे आज केवल अनैतिक माना जाता है कल गैरकानूनी हो सकता है। यह व्यापार और मानव अधिकार के संदर्भ में विशेष रूप से सत्य है। जैसा कि कंपनियां तेज़ी से मानव अधिकारों के जोखिम की पहचान और प्रबंधन को एक प्रमुख रणनीतिक लक्ष्य के रूप में देखते हैं, वे उम्मीद करते हैं कि उनके वकील न केवल तकनीकी कानूनी विशेषज्ञों के रूप में कार्य करें, बल्कि पक्के और नरम कानून के आधार पर मानवाधिकार प्रभावों की पहचान करे और बुद्धिमान सलाहकारों के रूप में सलाह दे।

26. सलाह जो केवल मौजूदा कानून के साथ तकनीकी अनुपालन पर आधारित है, मानवाधिकार पर प्रभाव की परवाह किए बिना, दुर्भाग्य से ग्राहकों के लिए व्यावसायिक जोखिमों की बड़ी तस्वीर मे मानवाधिकारों के हनन अस्पष्ट हो सकते है। इनमें ऐसे कारक शामिल हो सकते हैं जैसे कि प्रतिष्ठित नुकसान; खोए हुए अवसर; पूंजी बाजारों तक कम पहुंच; देरी की लागत; उच्च ब्याज या अधिक महंगा ऋण; शीर्ष प्रबंधन व्याकुलता; और प्रतिभा को काम पर रखने और बनाए रखने की क्षमता कम होना।

27. नतीजतन, व्यवसाय तेज़ी से व्यापार और मानवाधिकार के मामलों के संदर्भ में उभरते हुए अन्य कानूनी अभ्यास क्षेत्रो पर कानूनी सलाह और वकीलों से सेवाएं लेते है। उदाहरण स्वरूप:[22]

    - **अनिवार्य मानवाधिकार पर उचित परिश्रम कानून का अनुपालन।** जैसे-जैसे राज्य तेज़ी से मानव अधिकार उचित परिश्रम कानून को लागू करते हैं, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कंपनियों को उपयुक्त नीतियों, प्रक्रियाओं और उन प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करते हेतु नियम स्थापित करने की आवश्यकता होगी। कंपनियों को इन मामलों मे सलाह देने में वकील अहम भूमिका निभाएंगे।

- **आपराधिक कानून।** UNGP 23 (c) और सहित टिपण्णी उल्लेख करते है की कंपनियों को मानवाधिकारों के सकल हनन के जोखिम को कानूनी अनुपालन के रूप मे मानना चाहिए जो कि मानव अधिकारों के पक्के और नरम कानून पर आधारित हो।

- **पर्यावरण कानून।** पर्यावरण नुकसान का मानवाधिकार पर संभावित गंभीर प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता नुकसान की मान्यता मौलिक रूप से पर्यावरण कानून के अभ्यास को बदल देगी। पर्यावरण उचित परिश्रम से अलग, मानवाधिकार उचित परिश्रम पर्यावरण नियमों के तकनीकी अनुपालन तक सीमित नहीं है बल्कि कमजोर लोगों और समुदायों के अधिकारों का सम्मान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

- **कॉर्पोरेट प्रशासन।** प्रभावी होने के लिए, मानव अधिकार उचित परिश्रम को कंपनी के कॉर्पोरेट प्रशासन मे जड़ित होना चाहिए, यहां तक कि जहां मानव अधिकार उचित परिश्रम को न्याय द्वारा अनिवार्य नहीं किया गया हो। वकील कंपनियों की मदद कर सकते है उनके उचित आंतरिक शासन संरचना और उद्यम जोखिम प्रबंधन, नीतियां, और प्रक्रियाओ पर सलाह देकर।

- **विलय और अधिग्रहण (M&A)।** UNGP 17 प्रदान करता है कि किसी व्यवसाय संबंध मे मानव अधिकार उचित परिश्रम जल्द से जल्द आयोजित होना चाहिए, विशेष रूप से जहां कंपनियां मानव अधिकारों के जोखिम को अधिग्रहीत के विरासत मे ले सकती है। M&A वकील इस प्रक्रिया में मानव अधिकार और पर्यावरण जोखिमों की पहचान और जल्द सम्बोधन सुनिश्चित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- **वित्त।** UNGPs के तहत, वित्तीय संस्थानों को मानव अधिकारों के दुर्व्यवहार का कारण बनने या योगदान के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। जो वकील वित्तीय संस्थानों और निवेश बैंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हे यह समझना चाहिए कि व्यवसाय के रूप में उनके ग्राहकों की अपनी जिम्मेदारी है कि वे मानव अधिकारों का सम्मान करे, जिसमे शामिल उनके द्वारा किए गए ऋण और निवेश और उनके उधारकर्ताओं और शेयरधारकों द्वारा की गई कार्रवाई है। इस

जिम्मेदारी के लिए मौलिक आवश्यकता है कि मानवाधिकार परिश्रम का प्रयोग करें।

- **अनुबंध।** वकील अनुबंधों का गठन, प्रारूपण और प्रवर्तन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। एक अनुबंध उत्तोलन का प्रमुख स्रोत है जिसके माध्यम से कंपनी दोनों खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित कर सकती है अपने मानवाधिकार प्रदर्शन मे सुधार करने के लिए।

- **विवाद समाधान।** वकील प्रत्येक कल्पनीय प्रकृति के विवादों का प्रबंधन और समाधान करने मे कंपनियों की मदद करते हैं। इन विवादों को कई मंच पर संबोधित किया जा सकता है, जैसे की अदालत, प्रशासनिक एजेंसियां, विधायिकाओं द्वारा जांच, मध्यस्थता पैनल, गैर-न्यायिक शिकायत तंत्र जैसे OECD राष्ट्रीय संपर्क प्रक्रिया, साथ ही सामान्य और संदर्भ-विशिष्ट अनुप्रयोग के सहयोगपूर्ण और बहु-हितधारक शिकायत तंत्र, जिसमे UNGPs के तहत परिचालन स्तर की शिकायत तंत्र भी शामिल है।

- **एंटीट्रस्ट।** उनके मानवाधिकारों को संबोधित करने के लक्ष्यों मे, कंपनियों को पता होना चाहिए कि कुछ प्रतियोगियों के बीच सहयोग, भले ही उनके क्षेत्र में मानवाधिकारों के प्रदर्शन में सुधार लाने के इरादे से की गई हो, प्रतिस्पर्धा की चिंताओं को ट्रिगर कर सकता है। पर दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता नियामकों ने लिया है जलवायु परिवर्तन और स्थिरता से संबंधित आचरण के लिए छूट प्रदान किया है, जिसके प्रतिपादन एंटीट्रस्ट चिंता का विषय है।

- **रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण।** रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण वकील महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यह निर्धारित करने में कि कंपनियाँ हितधारको को क्या रिपोर्ट करती हैं अपने और हितधारको के मानव अधिकारों के हनन में शामिल होने से जो जोखिम होती है। मानवाधिकार जोखिम पर रिपोर्टिंग करना एक कंपनी के मानवाधिकार उचित परिश्रम का अनिवार्य हिस्सा है और ठीक रूप से विशिष्ट कमजोर लोगों और समुदाय के मानवाधिकार के हानी को प्रतिबिंबित करना चाहिए। अरबों अमेरिकी डॉलर निवेश किए जाते है इसे फर्म के परिसंपत्तियों मे जो अपने निवेश निर्णयों में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) को कारक बनाते है। यद्यपि 'S' या सामाजिक प्रभाव कारक मानवाधिकारों पर प्रभाव को शामिल करता है, आज

तक भ्रम की स्थिति है कि क्या रिपोर्ट किया जाना चाहिए, और क्या इसे किसी कंपनी के मानवाधिकार जोखिम पर किए गए पहचान और प्रतिक्रिया के परिणामों को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए। जब तक अधिक स्पष्टता प्राप्त नहीं हो जाती, ESG रिपोर्टिंग को किसी कंपनी के मानवाधिकार उचित परिश्रम के प्रति जिम्मेदारी का पर्याप्त कारक नहीं माना जाना चाहिए।

28. ऊपर सूचीबद्ध क्षेत्र केवल उदाहरण मात्र हैं। व्यापार और मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ और निहितार्थ श्रम और रोजगार के मामले, सरकारी संबंध, कर कानून, बौद्धिक संपत्ति, खनन कानून, बीमा, और दिवालियापन कानून, सहित कई अन्य कानूनी अभ्यास क्षेत्रों के सन्दर्भ में उभरते है।

अनुभाग 5: UNGPs के कारण कानूनी सेवाओं के अधिकार के संबंध में या वकीलों के पेशेवर कर्तव्यों के सामने क्या चुनौतियाँ स्थित हैं?

29. वह नियम जो कई क्षेत्रो मे कानूनी पेशे को नियंत्रित करते हैं, और संयुक्त राष्ट्र के वकीलों की भूमिका पर बुनियादी सिद्धांत (**UNBPRL**) के तहत, वकील 'न्याय प्रशासन के आवश्यक एजेंट' हैं और कानून का शासन स्थापित करने में तथा न्याय के व्यापक हितों को बढ़ावा देने मे मौलिक भूमिका निभाते है।

30. व्यवसाय द्वारा कानून का अनुपालन UNGPs के सभी स्तंभों का एक आधारित आवश्यकता है। वकील और कानूनी सेवाओ तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है एवं कानून के शासन और नियत प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है। वास्तव में, UNGPs के स्तंभ तीन इस दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य को दर्शाता है कि कमजोर व्यक्ति को विशेष रूप से कमी होती है अपने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी वकील तक पर्याप्त पहुंच की। कानूनी सलाह तक पहुंच के अधिकार को कम नहीं आंका जा सकता है, भले ही ग्राहक, या ग्राहक के कारण या विश्वास, अत्यधिक अलोकप्रिय है। यह व्यक्तियों और व्यवसायों सहित, हर प्रकृति के ग्राहकों पर लागू होता है। प्रत्येक व्यक्ति और संस्था को, व्यवसायों सहित, कानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व मांगने तलाश का अधिकार है जिससे मानव अधिकारों में शामिल मसलों का मूल्यांकन और उन दावों का जवाब दें सके। UNGPs कानूनी प्रतिनिधायन के अधिकार को बाधित नहीं करते हैं।

31. UNBPRL 18 तहत, वकीलों को स्वतंत्रता से साथ कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए; उन्हें उनके ग्राहकों या उनके ग्राहकों के विचार के साथ नहीं पहचाना जाना

चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि ग्राहक को निष्पक्ष सलाह प्रदान करे, जिसमें शामिल हैं वह जोखिम जो ग्राहक न जानना पसंद कर सकते हैं।

32. UNGPs वकीलों की पेशेवर जिम्मेदारियों को कम नहीं करते, जिसमें शामिल हैं कार्य करने का कर्तव्य, जो कि कानून और पेशेवर मानकों की सीमा के भीतर हो, उनके व्यापार ग्राहक के सर्वोत्तम हित में हो। इसमें शामिल है व्यवसायों को समाज और अपने प्रति जोखिम की पहचान और सम्बोधन पर सलाह देने की जो ग्राहक के मानव अधिकार और पर्यावरणीय प्रभाव मे भागीदार होने से हो सकती है। वकील-ग्राहक संबंध के बाहरी उम्मीदों के बावजूद इस कर्तव्य को पूरा किया जाना चाहिए, अपने पेशेवर और कानूनी जिम्मेदारियों के अनुपालन के अनुसार।

अनुभाग 6: UNGPs कानूनी फ़र्मों के लिए क्या माएने रखते है?

33. कानूनी फर्मों की, व्यावसायिक उद्यमों के रूप में, मानवाधिकारों का सम्मान करने की अपनी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी 'उनका आकार, क्षेत्र, परिचालन संदर्भ, स्वामित्व, और संरचना के बावजूद' व्यवसायों पर लागू होती है (UNGP 14)। अपने अद्वितीय पेशेवर कर्तव्यों के अधीन, इसमें कानूनी फर्म शामिल है। कानूनी फर्म अपने ग्राहकों को सलाह और सेवाएं प्रदान कर सकते हैं जो उन्हें स्थायी व्यावसायिक हित को पूरा करने मे सक्षम करेंगे जिससे वे मानवाधिकारों के दुरुपयोग को पहचानने, रोकने, कम करने और जहां उचित, अपने भागीदारी को दूर करने मे सफल होंगे। एसी सलाहकार सेवाएं प्रदान करने की क्षमता कानूनी फार्मों के लिए एक प्रमुख व्यवसाय के अवसर का संकेत देती है।

34. कानूनी फर्म एक ग्राहक की मूल्य श्रृंखला का हिस्सा हैं। जैसे ही ग्राहक अपने व्यवसाय और मानव अधिकारों के शासन, नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करेंगे, ग्राहक कानूनी फर्मों से उम्मीद करेंगे कि वे भी मानवाधिकारों का सम्मान करें एवं उनके कानूनी सेवाओ से संबंधित मानवाधिकार जोखिम को पहचाने और संबोधित करे। बड़ी कानूनी फर्म अभी से ही उनकी मूल्य श्रृंखलाओं के तहत आधुनिक गुलामी शासन पर रिपोर्ट कर रही हैं (जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूके में) एवं की गई कार्रवाइयों और कारवाही की प्रभावशीलता का विवरण दे रही है।

35. इसी समय, कानूनी फर्म अपने ग्राहकों के मानवाधिकारों का हनन को सक्षम करने के जोखिम का सामना कर रही है। उदाहरण के लिए, UN OHCHR ने हाल ही में कंपनियों द्वारा SLAPPs (रणनीतिक सार्वजनिक भागीदारी के खिलाफ मुकदमा) के बढ़ता उपयोग

की निंदा की जिससे मानवाधिकार रक्षक या पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दायर जाता है जिसका एकमात्र या प्राथमिक उद्देश्य उनकी गतिविधियों का सार्वजनिक विरोध, या आलोचना को नागरिक समाज अभिनेता पर बोझिल और महंगी मुकदमेबाजी से डराना और चुप कराना होता है।[23]

36. एक अन्य उदाहरण है गुमनाम शेल निगमों की स्थापना जो कि डिज़ाइन किया गया है उनके लाभकारी मालिकों के मानव अधिकार दुरुपयोग गतिविधियों मे अपनी भागीदारी को छिपाने पर सक्षम करने के लिए, जैसे कि क्लेप्टोक्रेट्स द्वारा चुराई गई संप्रभु संपत्ति की लॉन्ड्रिंग या उन उद्यमों की फंडिंग करना जो अवैध हथियारों की बिक्री करते है, मानव तस्करी, युद्ध अपराध और अन्य मानव अधिकारों के हनन मे शामिल है।

37. ऐसा आचरण कुछ अधिकार-क्षेत्रो में वैध हो सकता है। हालाँकि, UNGP 23 (b) प्रदान करता है कि जहाँ राष्ट्रीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के बीच संघर्ष हो, वहाँ कंपनियों को (तथा कानूनी फर्मों को, क्योंकि वे व्यावसायिक उद्यम है जिनकी अपने स्वयं की जिम्मेदारी है मानव अधिकारों का सम्मान करना), 'अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाने गए मानव अधिकार सिद्धांतों को सम्मान करना चाहिए'। इससे पहले संदर्भित, UNGP 23(c) की, अपेक्षा है कि 'जहां भी कंपनियां संचालित हो रही हो उन्हे गंभीर मानव अधिकार दुरुपयोग करने या योगदान देने के जोखिम को एक कानूनी अनुपालन मुद्दे के रूप में मानना चाहिए'। इस अनुपालन जोखिम को देखते हुए, कानूनी फर्म यह कर सकते है - और कुछ ने किया भी है - कि वे वकील-ग्राहक संबंध मे प्रवेश ना करे या इस संबंध को समाप्त करदे जहां कानूनी सेवाएं एसे दुरुपयोग का कारण या योगदान या सीधे तरह से जूड़ने की संभावना रखते हो।

38. मौलिक स्तर पर, एक कानूनी फर्म को तैयार रहना चाहिए इन सवालों पर विचार करने के लिए, एक ग्राहक संबंध की शुरुआती दौर में, और इसके मौजूदा होने के दौरान, ताकि वह अपने और अपने ग्राहकों की मानव अधिकार हनन मे भागीदारी के जोखिमों का आकलन कर सके और फर्म की प्रतिक्रिया प्रबंधित कर सके:

    - क्या ग्राहक के संचालन या मूल्य श्रृंखला में हो रहे मानव अधिकारों के दुरुपयोग में उसकी सेवाएं और सलाह संभावित कारण या योगदान बन सकते है?

    - वे हितधारक कौन हैं जो प्रभावित होंगे?

    - हितधारक के परिप्रेक्ष्य से नुकसान की गंभीरता क्या है?

- ग्राहक के संचालन, मूल्य चेन, प्रबंधन प्रणाली और व्यापार मॉडल के संदर्भ में अनुमित प्रभावों की संभावना क्या है?

- वकील की सलाह और सेवाओ तथा संभावित नुकसान के बीच के संबंध की प्रकृति क्या है (यानी, क्या सलाह या सेवाएं नुकसान का कारण बनेंगी या केवल उससे जुड़ी होंगी), और इसी तरह, ग्राहक के आचरण और संभावित नुकसान के बीच संबंध क्या है?

- यथोचित रूप से रोकने या इस तरह के नुकसान को कम करने के लिए फर्म क्या कदम उठा सकती है?

- क्या संभावित नुकसान इतना प्रबल और लगातार है कि फर्म को प्रतिनिधायन उपक्रम को नहीं करने पर विचार करना चाहिए?[24]

39. मानव अधिकार मुद्दों पर ग्राहकों को ठीक से सलाह देने और उनकी सेवा करने के लिए, कानूनी फर्मों के पास व्यवसाय और मानवाधिकार के नरम और पक्के कानून पर सलाह देने की पर्याप्त क्षमता और विशेषज्ञता होनी या विकसित करनी चाहिए। यह फर्म के आंतरिक और बाहरी व्यवसाय के लिए तथा मानवाधिकार विशेषज्ञ के लिए एक दोहरी भूमिका का सुझाव देता है। एक भूमिका है ग्राहकों को मानवाधिकारों पर स्पष्ट सलाह और सेवाएं प्रदान करना। दूसरी भूमिका है यह सुनिश्चित करना कि जो एसी सलाह सीधे प्रदान नहीं करते उनके पास अपने अभ्यास क्षेत्रों, जैसे कर, दिवालियापन, लेनदेन, मुकदमेबाजी, आदि, के मानवाधिकार निहितार्थ को समझने के लिए आंतरिक और बाहरी संसाधनों तक पर्याप्त पहुंच है और अभ्यास क्षेत्रों में साझा सीखने से लाभ उठाया जा सकता है।

अनुभाग 7: निष्कर्ष

40. स्वर्गीय प्रोफेसर जॉन रग्गी, UNGPs के लेखक, ने UNGPs को स्थिर पाठ के रूप में नहीं देखा था। बल्कि उन्होंने आशा व्यक्त की कि यूएनजीपी 'एक पुनरावृत्ति को ट्रिगर करेगा तीन वैश्विक के बीच बातचीत की प्रक्रिया शासन प्रणाली '- राज्य, व्यवसाय और नागरिक समाज - 'समय के साथ संचयी परिवर्तन का उत्पादन'। बल्कि उन्हे आशा थी कि UNGPs 'तीन वैश्विक शासन प्रणाली के बीच बातचीत की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति को ट्रिगर

करेगा' - राज्य, व्यवसाय और नागरिक समाज - 'समय के साथ संचयी परिवर्तन का उत्पादन करेगा'।[25] यह वास्तव मे हुआ है। UNGPs की गतिशीलता तथा पक्के और नरम कानून मानदंड, व्यवसायों की प्रथाओं और नीतियों (वकील एवं कानूनी फर्म सहित) और नागरिक समाज की वकालत में परिवर्तन उत्पन्न करने की क्षमता को बार-बार प्रदर्शित किया है।

41. UNGPs की गतिशील प्रकृति को देखते हुए, यह अद्यतन UNGPs के कानूनी पेशे पर प्रभाव के कहानी का अंत नहीं है। परिवर्तन जारी है, और प्रमुख विकास भविष्य में होगा। समय के साथ होने वाले विकास की प्रतीक्षा करना आकर्षक होगा, लेकिन वर्तमान मे वकीलों को ग्राहकों को सलाह और सेवा प्रदान करनी होगी। इसलिए UNGPs का कानूनी पेशे पर प्रभाव को सतत यात्रा के रूप मे देखना उपयोगी है, जिसमें यह अद्यतन समय में एक स्नैपशॉट है।

अनुभाग 9: प्रमुख संसाधन

1. संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और मानवाधिकार पर मार्गदर्शक सिद्धांत (2011) (UNGPs)
2. संयुक्त राष्ट्र OHCHR का मानव अधिकार का सम्मान करने के कॉर्पोरेट जिम्मेदारी पर व्याख्यात्मक गाइड (2012)
3. बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए OECD दिशानिर्देश (2011)
4. वकीलों की भूमिका पर संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांत | OHCHR (1990)
5. व्यापार और व्यापार वकीलों के लिए मानवाधिकार पर 2016 की IBA व्यावहारिक गाइड (2016)
6. व्यापार और व्यापार वकीलों के लिए मानवाधिकार पर IBA प्रैक्टिकल गाइड की संदर्भ अनुलग्नक (2016)
7. ISO 26000 - सामाजिक जिम्मेदारी (2010 मे पहले पेश किया गया)
8. संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कॉम्पैक्ट
9. संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कॉम्पैक्ट की चीन संजाल
10. व्यापार और मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का सक्रिय समूह
11. 10 पर संयुक्त रस्थर की व्यापार और मानव अधिकारों पर मार्गदर्शक सिद्धांत: न्यायालयों और कानूनी तंत्रों पर UNGPs का प्रभाव (2021)

12. जापानी सरकार की मानव अधिकार उचित परिश्रम पर दिशानिर्देश: जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखला मे मानव अधिकार सम्मान पर दिशानिर्देश: ビジネスと人権～責任あるバリューチェーンに向けて ～ (अंग्रेजी विवरण)
13. जिम्मेदार व्यापार आचरण पर OECD की उचित परिश्रम दिशानिर्देश (2018)
14. जिम्मेदार निवेश पर सिद्धांत (2020)
15. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन "बहुराष्ट्रीय उद्यम और सामाजिक नीति से संबंधित त्रिदलीय सिद्धांतों की घोषणा" (2017)
16. संयुक्त राष्ट्र महासभा, A/70/L.1, 'हमारी दुनिया को बदलना: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा' (2015)
17. संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प, A/76/300, 28 जुलाई 2022 मे अपनाया गया
18. जवाबदेही और उपाय परियोजना (ARP) रिपोर्ट्स
19. भूमध्य रेखा सिद्धांत
20. UNGP10+ (व्यापार और मानव अधिकार पर अगले दशक के लिए एक रोडमैप) संदर्भ के तौर पर।

योगदानकर्ता

Chair: Brabant, Stéphane

Andrade Lima Cardozo, Maria Izabel

Carnegie, Sara

Cassel, Douglass

Douvartzidis, Lara

Groulx Diggs, Elise

Lalani, Shaheeza

Maier, Bernhard

Scheltema, Martijn

Sherman, John

एंडनोट

1. अंतर्राष्ट्रीय बार संघ (2016) व्यापार और मानव अधकार पर वकीलों के लिए IBA की व्यावहारिक गाइड, IBA गाइड और रिपोर्ट | अंतर्राष्ट्रीय बार संघ (ibanet.org).

2. UN OHCHR (2011) व्यापार और मानव अधिकार पर मार्गदर्शक सिद्धांत: संयुक्त राष्ट्र के "रक्षा, सम्मान और उपचार" फ्रेमवर्क | OHCHR.
3. UN महासभा (28 जुलाई 2022) A/RES/76/300 (undocs.org).
4. यूरोपीय संघ (2022) कॉर्पोरेट स्थिरता उचित परिश्रम (europa.eu).
5. यूरोपीय संघ (2023) कॉर्पोरेट स्थिरता रेपोर्टिंग निदेश EUR-Lex – 32022L2464 – EN – EUR-Lex (europa.eu).
6. देखें Debevoise & Plimpton *10 पर UNGPs: न्यायालय और कानूनी तंत्र पर UNGPs का प्रभाव* full-report.pdf (debevoise.com).
7. *SERAP v. Nigeria*: निर्णय क्रमांक. ECW/CCJ/ JUD/18/12, दिसंबर 14, 2022 का निर्णय.
8. Vedanta Resources Plc and another v Lungowe and others [2019] UKSC 20; *Okpabi and others v Royal Dutch Shell Plc and another* [2021] UKSC 3.
9. *Nevsun Resources Ltd. v. Araya* [2020] 1 S.C.R. 166.
10. मानव अधिकार पर अंतर-अमेरिकी न्यायालय, *Case Of The Miskito Divers (Lemoth Morris Et Al.) v Honduras* (31 अगस्त 2021).
11. *University of Stellenbosch Legal Aid Clinic and Others v Minister of Justice And Correctional Services and Others* (16703/14) [2015] ZAWCHC 99; 2015 (5) SA 221 (WCC); [2015] 3 All SA 644 (WCC); (2015) 36 ILJ 2558 (WCC) (8 July 2015).
12. *Oguru, Efanga & Veeniging Milieudefensie v Shell Petroleum NV*, अपील की अदालत हेग 200.126.804 (case a) + 200.126.834 (case b) (29 January 2021).
13. *Milieudefensie v Shell* (25 June 2021) C/09/571932 / HA ZA 19-379 (अंग्रेजी विवरण); ECLI number: ECLI:NL:RBDHA:2021:5337 (डच विवरण).
14. मामला क्रमांक. 2020/32777. प्रस्ताव की सूचना दायर 20 अक्टूबर 2020, दक्षिण अफ्रीका का उच्च न्यायालय ग्वाटेंग स्थानीय प्रभाग, जोहान्सबर्ग, Founding-affidavit-as-served-REDACTED-21.10.2020.pdf (childrenofkabwe.com); देखे व्यापार और मानव अधिकार संसाधन केंद्र, एंग्लो अमेरिकन साउथ अफ्रीका लिमिटेड के खिलाफ क्लास एक्शन मुकदमा (रे सीसा विषाक्तता, जाम्बिया), https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/lawsuit-against-anglo-american-south-africa-ltd-re-lead-poisoning-zambia/.
15. जलवायु परिवर्तन मुकदमेबाजी डेटाबेस, *Asmania et al v Holcim*, http://climatecasechart.com/non-us-case/four-islanders-of-pari-v-holcim/; जलवायु परिवर्तन मुकदमेबाजी डेटाबेस, *Luciano Lliyua v RWE AG*, https://climatecasechart.com/non-us-case/lliuya-v-rwe-ag/.
16. जलवायु परिवर्तन मुकदमेबाजी डेटाबेस, *Friends of the Earth et al v Total (Les Amis de la Terre v Total)*, https://climatecasechart.com/non-us-case/friends-of-the-earth-et-al-v-total/;

Duty of Vigilance Radar, Ongoing Cases, https://vigilance-plan.org/court-cases-under-the-duty-of-vigilance-law/.

17. Clearly Gottleib (29 जनवरी 2020) व्यापार और मानवाधिकार मध्यस्थता पर हेग नियम का शुभारंभ, https://www.clearygottlieb.com/-/media/files/ alert-memos-2020/the-launch-of-the-hague-rules-on-business-and-human-rights-arbitration.pdf.
18. *Urbaser v Argentina* (8 दिसंबर 2016) ICSID मामला क्रमांक. ARB/07/26; David Aven et al v Costa Rica (18 सितंबर 2018) Case No. UNCT/15/3.
19. अफ्रीकी मध्यस्थता अकादमी, *अफ्रीका मध्यस्थता अकादमी - अफ्रीका के कानूनी भविष्य में निवेश करना.*
20. OECD (2023) ज़िम्मेदार व्यापार आचरण पर बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए दिशानिर्देश *https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/*.
21. *मानव अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय निगमों और अन्य व्यावसायिक उद्यमों के मुद्दे पर सक्रिय समूह के अधिदेश; जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मानव अधिकारों के पदोन्नति और संरक्षण पर विशेष प्रतिवेदक; एक सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और स्थिर पर्यावरण का आनंद से संबंधित मानव अधिकार के दायित्वों के मुद्दे पर विशेष प्रतिवेदक; पर्यावरणीय उचित प्रबंधन तथा खतरनाक पदार्थों और कचरे से निपटने से मानव अधिकार के लिए निहितार्थ पर विशेष प्रतिवेदक एवं सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के मानवाधिकारों पर विशेष प्रतिवेदक, UN मानव अधिकारों पर सक्रिय समूह*, AL OTH 53/2023, 26 जून 2023, यहाँ उपलब्ध https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28094
22. 2016 प्रैक्टिकल गाइड की धारा 3 में उन अभ्यास क्षेत्रो के उदाहरणों को सूचीबद्ध किया गया है जहां व्यापार और मानव अधिकारों के प्रभाव का ज्ञान महत्वपूर्ण हैं।
23. संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायोग का कार्यालय, व्यापार और मानव अधिकारों पर मार्गदर्शक सिद्धांत: मानवाधिकार रक्षकों के लिए सम्मान सुनिश्चित करने पर मार्गदर्शन - मानव अधिकारों के मुद्दों और अंतरराष्ट्रीय निगम और अन्य व्यावसायिक उद्यमों पर सक्रिय समूह की रिपोर्ट, UN Human Rights Working Group A/HRC/47/39/ Add.2: A/HRC/47/39/Add.2: The Guiding Principles on Business and Human Rights: guidance on ensuring respect for human rights defenders - Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises | OHCHR.
24. अधिक जानकारी के लिए, IBA संदर्भ अनुलग्नक की धारा 6.3 देखें, document (ibanet.org).

25. रग्गी (2018) व्यापार और मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों का सामाजिक निर्माण.